



## समायोजति सकल राजस्व

### प्रीलमिस के लिये:

समायोजति सकल राजस्व, दूरसंचार वभिाग, लाइसेंसिंग फाइनेंस पॉलिसी वगि, उच्चतम न्यायालय

### मेन्स के लिये:

भारत की प्रगतमें दूरसंचार क्षेत्र का योगदान, दूरसंचार क्षेत्र से संबंधति चुनौतियों और मुद्दे

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने दूरसंचार ऑपरेटर्स द्वारा समायोजति सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue- AGR) भुगतान के संदर्भ में समयसीमा में छूट प्रदान की है।

### महत्त्वपूर्ण बढि

- दूरसंचार वभिाग (Department of Telecommunication- DoT) की लाइसेंसिंग फाइनेंस पॉलिसी वगि (The Licensing Finance Policy Wing) ने सभी वभिागों को समायोजति सकल राजस्व (AGR) से संबंधति बकाया राशिके भुगतान में वफिल रहे दूरसंचार ऑपरेटर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का नरिदेश दिया है।
- इस आदेश में दूरसंचार ऑपरेटर्स द्वारा भुगतान की जाने वाली राशिके कोई बदलाव नहीं किया गया है अपत्ति भुगतान की समयसीमा में वृद्धिकी गई है।
- ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को लगभग 92,000 करोड़ रुपए के बकाया समायोजति सकल राजस्व का भुगतान करने का आदेश दिया था जसि सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती संबंधी याचिका को खारजि करते हुए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने के लिये एक समयसीमा नरिधारति की थी। इस समयसीमा में भुगतान न कर पाने वाले सेवा प्रदाताओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार ने यह नरिदेश दिया है।

### सरकार द्वारा भुगतान समयसीमा में वृद्धिके वभिन्न वर्गों पर प्रभाव

#### सेवा प्रदाताओं पर प्रभाव

यह आदेश दूरसंचार सेवा प्रदाताओं मुख्य रूप से भारती एयरटेल एवं वोडाफोन आइडिया के संचालकों के लिये एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है, अन्यथा इन सेवा प्रदाताओं को 23 जनवरी तक भुगतान न करने पर संभावति अवमानना कार्रवाई का सामना करना पड़ता।

ध्यातव्य है कि भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया पर दूरसंचार वभिाग का लगभग 88,624 करोड़ रुपए बकाया है। जबकि रिलायंस जियो ने 23 जनवरी को 195 करोड़ रुपए का बकाया चुका दिया है।

#### उपभोक्ताओं पर प्रभाव

- हाल के कुछ वर्षों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच में अत्यधिक प्रतस्पर्द्धा के कारण दूरसंचार सेवाओं के मूल्य में काफी कमी आ गई थी कत्ति सरकार के समायोजति सकल राजस्व के भुगतान संबंधी आदेश के बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया जैसे सेवा प्रदाताओं पर अत्यधिक राजस्व भार पड़ने से सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है।
- सरकार के इस आदेश से इन सेवा प्रदाताओं को भुगतान के लिये और समय प्राप्त होने से दूरसंचार सेवा बाजार में प्रतस्पर्द्धा में पुनः वृद्धि हो सकती है जसिका लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा।

- ध्यातव्य है कि हाल के कुछ समय में वोडाफोन जैसी सेवा प्रदाता कंपनी देश से अपने व्यापार को समेटने का संकेत दे रही थीं कति सरकार के इस आदेश से इस क्षेत्र में स्थायित्व की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही उपभोक्ताओं को कम दाम में नरितर सेवा प्राप्त हो सकेगी।

## म्यूचुअल फंड एवं बैंकों पर प्रभाव

- समायोजति सकल राजस्व संबंधी मुद्दे ने म्यूचुअल फंड और बैंकिंग क्षेत्र को चिंता में डाल दिया था क्योंकि दूरसंचार क्षेत्र अत्यधिक लाभान्वति क्षेत्र है और इस क्षेत्र का संकट बैंकिंग क्षेत्र को भी प्रभावति करता है।
- ध्यातव्य है कि अकेले वोडाफोन-आइडिया पर 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसका उपयोग उसने पछिले कुछ वर्षों में बुनयादी ढाँचे और फंड स्पेक्ट्रम भुगतान का वसितार करने के लिये किया है। इससे इन सेवा प्रदाताओं को समायोजति सकल राजस्व भुगतान के लिये समय मलि जाएगा जिससे वे अपनी बाज़ार क्षमता का वसितार और बैंक का भुगतान आसानी से कर सकेंगे।

## इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के नरिणय

- 24 अक्टूबर, 2019 को न्यायालय ने DoT की AGR की परभिषा से सहमत वियक्त की और कहा कि कंपनयियों को ब्याज एवं जुर्माने के साथ सभी बकाया राशिका भुगतान करना होगा।
- ध्यातव्य है कि भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने DoT को समयसीमा में ढील देने के लिये मनाने की कोशशि की और असफल होने के बाद फैसेले की समीक्षा के लिये न्यायालय का रुख किया था।
- न्यायालय ने पछिले हफ्ते समीक्षा याचिका को खारजि कर दिया है और साथ ही AGR शेष के भुगतान की समयसीमा भी नहीं बढ़ाई है।
- हालाँकि उच्चतम न्यायालय ने कंपनयियों में संशोधन की याचिका (Companies Modification Plea) को सुनने के लिये सहमत वियक्त की है।

## स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/adjusted-gross-revenue-payment-deadline-increased>

